



## राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2023

संदर्भ: शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने इंडिया रैंकिंग 2023 जारी की।

NIRF क्या है?

- सितंबर 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD), जिसे अब शिक्षा मंत्रालय (MoE) के रूप में जाना जाता है, द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया था। यह फ्रेमवर्क विभिन्न मापदंडों के आधार पर भारत में संस्थानों को रैंक करने के लिए एक पद्धति प्रदान करता है।
- रैंकिंग छह मापदंडों और कोष्ठक में महत्त्व पर आधारित है:
  - शिक्षण-अधिगम और संसाधन (0.3)
  - अनुसंधान और पेशेवर अभ्यास (0.3)
  - स्नातक परिणाम (0.2)
  - आउटरीच और समावेशिता (0.1)
  - संस्था के बारे में धारणा (0.1)
- रैंकिंग शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान आउटपुट, छात्र परिणामों, समावेशिता और सार्वजनिक धारणा के आधार पर संस्थानों का आकलन करती है।
- इस रैंकिंग में शामिल संस्थान
  - भारत रैंकिंग 2023 में कुल 5,543 अद्वितीय संस्थानों ने भाग लिया।
  - इन संस्थानों ने विभिन्न श्रेणियों में रैंकिंग के लिए 8,686 आवेदन जमा किए।
  - संस्थागत भागीदारी में वृद्धि एक निष्पक्ष और पारदर्शी अभ्यास के रूप में रैंकिंग की मान्यता को दर्शाती है।
  - अनन्य आवेदकों की संख्या 2016 में 2,426 से बढ़कर 2023 में 5,543 हो गई है।
  - आवेदनों की कुल संख्या 2016 में 3,565 से बढ़कर 2023 में 8,686 हो गई है।
  - 2016 में भारत रैंकिंग की शुरुआत के बाद से कुल मिलाकर 100 संस्थानों को विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और इंजीनियरिंग में स्थान दिया गया है।
  - 2022 के बाद से प्रबंधन और फार्मैसी में रैंक किए गए संस्थानों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है।
  - वास्तुकला, कानून, चिकित्सा, दंत चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान जैसे विषय विभागों में रैंकिंग प्राप्त करने वाली संस्थानों की संख्या कम है।
  - अतिरिक्त रैंकिंग को कुछ श्रेणियों में 101-150 और 151-200 के रैंक बैंड में बांटा गया है।

भारतीय रैंकिंग 2023 की मुख्य विशेषताएं

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने लगातार पांचवें वर्ष (2019-2023) और इंजीनियरिंग में लगातार आठवें वर्ष (2016-2023) समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है।
- समग्र श्रेणी में शीर्ष 100 में 44 सीएफटीआई/सीएफयू आईएनआई, 24 राज्य विश्वविद्यालय, 13 डीमड विश्वविद्यालय, 18 निजी विश्वविद्यालय, 4 कृषि और संबद्ध क्षेत्र के संस्थान और 3 प्रबंधन संस्थान शामिल हैं।
- भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु ने लगातार आठवें साल (2016-2023) में विश्वविद्यालयों श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करता है और अनुसंधान संस्थानों श्रेणी में लगातार तीसरे वर्ष (2021-2023) के लिए।
- आईआईएम अहमदाबाद प्रबंधन विषय में चौथे संयुक्त वर्ष (2020-2023) में शीर्ष स्थान पर रहा है।
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली लगातार छठे वर्ष (2018-2023) चिकित्सा में शीर्ष स्थान पर काबिज है।
- राष्ट्रीय औद्योगिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, जामिया हमदर्द को पछाड़ते हुए पहली बार फार्मैसी रैंकिंग में सबसे ऊपर है।
- मिरांडा हाउस सातवें वर्ष (2017-2023) भी कॉलेजों में पहला स्थान की बनाए है।
- आईआईटी रुड़की वास्तुकला विषय में लगातार तीसरे वर्ष (2021-2023) पहले स्थान पर है।
- नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु ने कानून में लगातार छठे वर्ष (2018-2023) के लिए अपनी पहली स्थान प्राप्त की है।
- रैंकिंग में शीर्ष 10 कॉलेजों में दिल्ली के पांच कॉलेज शामिल हैं।
- सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर है।
- नवाचार में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर अब्जल रहा।

## Face to Face Centres





6 June, 2023

## भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट

**प्रसंग:** पर्यावरण स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए, NHAI की पहली 'वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट', श्री नितिन गडकरी द्वारा रिपोर्ट का अनावरण किया गया।

- NHAI ने वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक ईंधन की खपत में कमी के जरिए प्रत्यक्ष उत्सर्जन में **18.44% की कमी** की है।
- अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को कम करने के लिए **स्वच्छ और हरित ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण** के प्रयास किए जा रहे हैं।
- ऊर्जा खपत, संचालन, परिवहन और यात्रा से **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** वित्त वर्ष 2020-21 में **9.7%** और वित्त वर्ष **2021-22 में 2%** कम हुआ।
- संचालन में **ऊर्जा तीव्रता 37%** और वित्त वर्ष 2021-22 में **27% कम हुई**।
- **FASTag** के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह ने **97%** से अधिक पैठ हासिल कर ली है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट में कमी आई है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में **फ्लाई-ऐश और प्लास्टिक कचरे** जैसी पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग किया जाता है।
- **20 राज्यों में वन्यजीव क्रॉसिंग वन्यजीवों की रक्षा करते हैं** और मानव-पशु संघर्ष को कम करते हैं।
- **वृक्षारोपण अभियान** के परिणामस्वरूप वाहन उत्सर्जन को ऑफसेट करने के लिए लगभग 2.74 करोड़ पौधे लगाए गए हैं।
- वृक्षारोपण अभियान के लिए **SRML, स्वयं सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों** सहित हितधारकों के साथ सहयोगात्मक साझेदारी बनाई जाती है।
- NHAI ने एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया, जिसमें 114 स्थानों पर एक ही दिन में लगभग 1.1 लाख पौधे लगाए गए।
- एनएचआई ने **महिलाओं और वंचित समुदायों के रोजगार में वृद्धि** की है।
- सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट **ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (GRI) के दिशा-निर्देशों का पालन करती है** और तीसरे पक्ष द्वारा बाह्य रूप से आश्वस्त होती है।
- रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के ढांचे के अनुसार **बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में 'ग्रीन फाइनेंस' को सक्षम कर सकती है**।
- NHAI आर्थिक व्यवहार्यता, सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध है।

### एनएचआई

- NHAI सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत **1988 में गठित एक वैधानिक निकाय** है।
- भारत में **राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन** के लिए जिम्मेदार है।
- NHAI **स्वायत्त रूप से संचालित होता है** और कुशल और सुरक्षित राजमार्ग संचालन पर ध्यान केंद्रित करता है।
- राष्ट्रीय राजमार्गों पर **टोल प्लाजा का संचालन और रखरखाव NHAI के दायरे में आता है**।
- प्राधिकरण समय पर और गुणवत्तापूर्ण परियोजना निष्पादन के लिए हितधारकों के साथ सहयोग करता है।
- यह सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए **स्थिरता, सुरक्षा और सुविधा पर जोर देती है**।

### वैश्विक रिपोर्टिंग पहल क्या है?

GRI (वैश्विक रिपोर्टिंग पहल) एक स्वतंत्र, अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो व्यवसायों और अन्य संगठनों को उनके प्रभावों की जिम्मेदारी लेने में मदद करता है, उन्हें उन प्रभावों को **संप्रेषित करने के लिए वैश्विक आम भाषा प्रदान करता है**।

## प्रतिकूल कब्जा कानून

**संदर्भ:** विधि आयोग ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कानून में किसी भी तरह के बदलाव को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

- प्रतिकूल कब्जा एक कानूनी अवधारणा है जो इस **विचार पर आधारित है कि भूमि को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए बल्कि उपयोग में लाया जाना चाहिए**।
- यह एक **निर्दिष्ट अवधि के लिए भूमि के कब्जे वाले व्यक्ति को स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने की अनुमति देता है**, भले ही उसका मूल स्वामित्व न हो।
- प्रतिकूल कब्जे के पीछे तर्क में **भूमि के स्वामित्व की लंबी अनिश्चितता से बचना और निष्क्रिय भूमि के उत्पादक उपयोग को बढ़ावा देना** शामिल है।
- विधि आयोग की रिपोर्ट प्रतिकूल कब्जे का समर्थन करती है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग लंबे समय तक अपने अधिकारों को लागू करने की उपेक्षा करते हैं, उन्हें भूमि पर **पुनः दावा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए**।
- प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा **प्राचीन काल से चली आ रही है**, इसकी जड़ें **हम्मुराबी कोड में पाई जाती हैं**।
- **परिसीमा अधिनियम, 1963** प्रतिकूल कब्जे में बदलाव लाया, और इसने असली मालिक की स्थिति को मजबूत किया और सबूत के बोझ को दावेदार पर स्थानांतरित कर दिया।

## Face to Face Centres





6 June, 2023

- सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिकूल कब्जे के कानून को तर्कहीन और अनुपातहीन मानते हुए इसमें बदलाव की सिफारिश की है।
- असहमतिपूर्ण राय असली मालिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों और अदालत प्रणाली पर बोझ का हवाला देते हुए प्रतिकूल कब्जे के कानून को खत्म करने का सुझाव देती है, ।
- वर्तमान विधि आयोग इस मुद्दे के महत्व और 2008 से लंबित संदर्भ को पहचानते हुए इस विषय पर नए सिरे से विचार-विमर्श कर रहा है।

## विधि आयोग

- भारत का विधि आयोग कानूनी अनुसंधान और कानून सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक गैर-सांविधिक निकाय है।
- स्वतंत्रता के बाद, यह पहली बार 1955 में गठित किया गया था और तब से कानून से संबंधित विभिन्न अध्ययन करने और कानूनी सुधारों के लिए सिफारिशों करने के लिए नियमित आधार पर इसका पुनर्गठन किया गया है।
- विधि आयोग का प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा कानूनों की समीक्षा और आधुनिकीकरण करना, कानूनी सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना और समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए नए कानून का प्रस्ताव करना है।
- आयोग में एक अध्यक्ष होता है, जो आमतौर पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, और कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और चिकित्सकों सहित कई सदस्य होते हैं।
- विधि आयोग की सिफारिशें और रिपोर्ट महत्वपूर्ण महत्व रखती हैं, किन्तु ये केवल सलाह होती हैं, और अक्सर विधायी परिवर्तनों के आधार के रूप में काम करती हैं, जो देश के कानूनी ढांचे को आकार देने और सुधारने में मदद करती हैं।

## NEWS IN BETWEEN THE LINES

### "रियाद में ईरानी दूतावास को फिर से खोलने की तैयारी"

#### संदर्भ:

ईरान सात साल के बंद के बाद सऊदी अरब के रियाद में अपने दूतावास को फिर से खोलने के लिए तैयार है।

#### मुख्य विशेषताएं:

- शिया धर्मगुरु निम्न अल-निम्न को फांसी दिए जाने के विरोध के दौरान तेहरान में उसके दूतावास और मशहद में वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद सऊदी अरब ने वर्ष 2016 में ईरान के साथ संबंध तोड़ लिए थे।
- रियाद में ईरान का दूतावास, जेद्दा में इसका वाणिज्य दूतावास और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के प्रतिनिधि कार्यालय को आधिकारिक तौर पर फिर से खोल दिया जाएगा।
- 10 मार्च को चीन में हुए सुलह समझौते ने पूरे पश्चिम एशिया में संघर्ष क्षेत्रों में वर्षों की कलह और विरोधी पक्षों के समर्थन के बाद ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों में आश्चर्यजनक बदलाव को चिह्नित किया।

#### रियाद में दूतावास फिर से खोलने का कारण:

- रियाद में ईरानी दूतावास को फिर से खोलना ईरान और सऊदी अरब के बीच कूटनीतिक संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- दूतावास को फिर से खोलकर, ईरान का उद्देश्य बेहतर संचार को बढ़ावा देना, द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करना और सऊदी अरब के साथ आपसी समझ को बढ़ावा देना है।

#### ईरान का कूटनीतिक मिशन:

सऊदी अरब में ईरान के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अलीरजा इनायती की अध्यक्षता में ईरान का राजनयिक/कूटनीतिक मिशन जिम्मेदार होगा।



### "जैविक कपास प्रमाणन के लिए उपग्रह और एआई"

#### संदर्भ:

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड (GOTS) भारत में जैविक कपास के खेतों को प्रमाणित करने के लिए उपग्रह छवियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करने के लिए सहयोग कर रहे हैं।

#### मुख्य विशेषताएं:

- पहल का उद्देश्य कपास के खेतों की पहचान करना है, जो जैविक खेती के मानकों को पूरा करते हैं तथा जैविक खेती के संक्रमण का समर्थन करते हैं।
- भारत में कपास के खेतों को वर्गीकृत करने के लिए एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए ईएसए के उपग्रह डेटा का उपयोग किया जाएगा।
- यह परियोजना जीओटीएस को विशिष्ट क्षेत्रों में जैविक कपास की पैदावार का सटीक अनुमान लगाने में मदद करेगी।
- जीओटीएस जैविक वस्त्रों को बढ़ावा देने वाले संगठनों का गठबंधन है।



## Face to Face Centres





	<p><b>सहयोग:</b> ESA, GOTS और AI कंपनी Marple के बीच सहयोग का उद्देश्य जैविक कपास के खेतों को प्रमाणित करने के लिए उपग्रह डेटा और AI तकनीक को संयोजित करना है। <b>जैविक कपास की पैदावार:</b> जैविक कपास की उपज किसी दिए गए क्षेत्र या क्षेत्र में उत्पादित जैविक कपास की मात्रा को संदर्भित करती है। यह खेतों से काटे गए कपास की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जो जैविक खेती प्रथाओं का पालन करते हैं, जैसे कि सिंथेटिक कीटनाशकों से बचना और पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ावा देना। <b>सहयोग का उद्देश्य:</b> सहयोग का प्राथमिक उद्देश्य जैविक कपास प्रमाणन की अखंडता को मजबूत करना और आपूर्ति श्रृंखला में धोखाधड़ी को रोकना है। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य प्रमाणित जैविक क्षेत्र में छोटे पैमाने के किसानों की भागीदारी बढ़ाना और कपड़ा उद्योग के भीतर जैविक कपास की बढ़ती उपभोक्ता मांग को पूरा करना है।</p>
<p><b>"कैंसर को लक्षित करने वाले टीके: नया शोध"</b></p>	<p><b>संदर्भ:</b> हाल के शोध से पता चलता है कि इम्यूनोथेरेपी के संयोजन में एमआरएनए-आधारित टीकों ने मेलेनोमा के प्रसार को कम करने और त्वचा कैंसर रोगियों के लिए जीवित रहने की दर में सुधार करने के लिए आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। <b>मुख्य विशेषताएं:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ मॉडर्न और मर्क (Moderna and Merck) के एक प्रायोगिक एमआरएनए-आधारित वैक्सीन ने अकेले इम्यूनोथेरेपी की तुलना में इम्यूनोथेरेपी के साथ संयुक्त होने पर मध्य-चरण के परीक्षण में मेलेनोमा के प्रसार के जोखिम को 65% तक कम कर दिया।</li> <li>➤ मर्क के कीट्रूडा (Merck's Keytruda) के साथ दिए जाने पर अनुकूलित एमआरएनए वैक्सीन ने अकेले कीट्रूडा का उपयोग करने की तुलना में मृत्यु या त्वचा कैंसर की पुनरावृत्ति के जोखिम को 44% तक कम कर दिया।</li> <li>➤ mRNA तकनीक, जिसे COVID-19 महामारी के दौरान प्रमुखता मिली, में व्यक्तिगत टीके विकसित करने की क्षमता है जो रोगी के ट्यूमर में विशिष्ट कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करती है।</li> <li>➤ mRNA के टीके, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करने वाली दवाओं के साथ जोड़े जाते हैं, ट्यूमर पर मौजूद प्रोटीन को चुनिंदा रूप से लक्षित कर सकते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ ऊतकों को नुकसान को कम करते हुए कैंसर कोशिकाओं को मारने की अनुमति देती है।</li> </ul> <p><b>सहयोग:</b> मर्क (Merck) और मॉडर्ना (Moderna) जैसी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के बीच सहयोग, साथ ही बायोएनटेक और ग्रिटस्टोन बायो इंक के साथ फाइजर की साझेदारी विभिन्न प्रकार के कैंसर को लक्षित करने के लिए एमआरएनए वैक्सीन तकनीक के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने वाली दवाओं का संयोजन कर रही है।</p>
<p><b>"न्याय विकास पोर्टल: सीएसएस कार्यान्वयन की निगरानी"</b></p>	<p><b>संदर्भ:</b> जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme: CSS) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए न्याय विकास पोर्टल विकसित किया गया है। <b>मुख्य विशेषताएं:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ न्याय विकास पोर्टल सूचना तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों को लॉग इन करने के चार कुशल तरीके प्रदान करता है।</li> <li>➤ न्याय विभाग 1993-94 से CSS को लागू कर रहा है, जो न्यायिक अधिकारियों के लिए कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है।</li> <li>➤ वकीलों और वादियों की सुविधा के लिए वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों जैसी नई सुविधाओं के साथ इस योजना को 31.03.2021 से आगे बढ़ाया गया है।</li> </ul> <p><b>न्याय विकास पोर्टल क्या है?</b> न्याय विकास पोर्टल जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बनाया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह हितधारकों को फंडिंग, प्रलेखन, परियोजना निगरानी और अनुमोदन से संबंधित जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देता है। <b>फंड शेयरिंग:</b> योजना के लिए फंड शेयरिंग पैटर्न केंद्र और राज्यों (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर) के बीच 60:40 है। उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए पैटर्न 90:10 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों को 100% फंडिंग मिलती है।</p>

